Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 20, Issue No. 4, October-2023, ISSN 2230-7540

रोजगार के क्षेत्र पर विभिन्न गरीबी योजनाओं की प्रभाव का विश्लेषित करना

Ruchi Soni[1]*, Dr. Ravi Prakash Pandey[2], Dr. Prabhakar Singh[3]

[1] Research Scholar of Commerce, A.P.S. University Rewa, Madhya Pradesh

[2] Prof. of Commerce, Sarda Mahavidyalaya Sarlanagar, Maihar, Madhya Pradesh.

[3] Prof. of Commerce, S.G.S. Govt. Auto. P.G. College Sidhi, Madhya Pradesh.

सार - *भारत में योजना की शुरुआत से ही गरीबी उन्मूलन विकास नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। भारत में विभिन्न गरीबी निवारण, रोजगार सृजन और बुनियादी सेवा कार्यक्रम दशकों से चल रहे हैं। चल रहे सुधार गरीबी हटाने और विशेष रूप से राज्यों में व्यापक विविधताओं और ग्रामीण-शहरी विभाजन को संबोधित करने को बहुत महत्व देते हैं। गरीबी-विरोधी रणनीति के तीन व्यापक घटक हैंरू आर्थिक विकास को बढ़ावा देनाय मानव विकास को बढ़ावा देनाय और गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को संबोधित करने के लिए गरीबी उन्मूलन के लक्षित कार्यक्रम। गरीबों पर लक्षित विभिन्न कार्यक्रमों को हाल के वर्षों में सुव्यवस्थित और मजबूत किया गया है, जिसमें नरेगा भी शामिल है। उद्योग पर वृहद-आर्थिक वातावरण के प्रभाव से अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से अधिक नौकरियाँ और उच्च स्तर की मजदूरी और आय उत्पन्न होती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बाह्योन्मुख नीतिगत परिवर्तनों की श्रृंखला अर्थात् औद्योगिक सुधार, राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, व्यापार नीति सुधार आदि पेश किए गए। एक आर्थिक सुधार ऐतिहासिक रूप से विकसित हो रहा है और तकनीकी क्रांति द्वारा अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।*

कीवर्ड - *गरीबी, रोजगार, कार्यक्रम, भारत, पीढ़ी*

----------X----------

परिचय

19वीं सदी के मध्य और 20वीं सदी की शुरुआत में, हमने औपनिवेशिक युग के दौरान गरीबी में वृद्धि देखी। औपनिवेशिक नियमों ने बेगार कारीगरों को खेती में स्थानांतरित कर दिया और देश को धीरे-धीरे भूमि-जीवन, अशिक्षित श्रम और कम दक्षता में समृद्ध प्रांत में बदल दिया। इस प्रकार, इसने देश को श्रम, पूंजी और ज्ञान में दुर्लभ बना दिया।

गरीबी उन्मूलन राहत, या कटौती, तरीकों का एक समूह है, जिसके द्वारा सरकारों की नीतियां लोगों को स्थायी रूप से गरीबी रेखा से बाहर निकालने का इरादा रखती हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2020 के अनुसार, भारत 0.123 के एमपीआई स्कोर के साथ 107 देशों में से 62वें स्थान पर है। हाल ही में एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि छह बहुआयामी गरीब लोगों में से पांच निचली जनजातियों या जातियों से थे, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार, 27.5 के स्कोर के साथ, भारत 116 देशों में से 101 वें स्थान पर है, और आंकड़ों के अनुसार, भूख का स्तर गंभीर है.

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1950 में भारत में गरीबी को कम करने के लिए विभिन्न पहल की गईं, मिन्हास ने भारत में गरीबी दर का अनुमान लगाया, और 1960 में भारत और उसके बाद के विभिन्न अन्य लोगों के लिए गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए एक कार्य

www.ignited.in

समूह का गठन किया गया। स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में पहली बार, भारत की तीसरी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में गरीबी को एक राष्ट्रीय मुद्दा माना गया। दो मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, गरीबी हटाओ ग्गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, डी.डी. धार ने आय के बेहतर वितरण, उच्च विकास दर को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास के माध्यम से 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की और लॉन्च की।

साहित्य की समीक्षा

प्रमोद और चुडासमा (2020) विकासशील देशों में गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को संबोधित करने के लिए कई भागीदारी और समुदाय-मांग-संचालित दृष्टिकोण उभरे हैं। वर्तमान अध्ययन कारण संबंधी तर्क को प्रदर्शित करने के लिए तैनात फजी कॉग्निटिव मैप्स (एफसीएम) की सहायता से भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करता है। यह एफसीएम-आधारित सिमुलेशन के माध्यम से है कि अध्ययन मौजूदा गरीबी उन्मूलन दृष्टिकोण की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है, जिसमें सामुदायिक संगठन आधारित सूक्ष्म-वित्तपोषण, क्षमता और सामाजिक सुरक्षा, बाजार-आधारित और सुशासन शामिल हैं। हमारे निष्कर्ष, कुछ हद तक, गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की संपूरकता की पुष्टि करते हैं जिन्हें व्यापक गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए एक साथ लागू करने की आवश्यकता है। एफसीएम-आधारित सिमुलेशन गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के तत्वों को शामिल करते हुए एक एकीकृत और बहुआयामी दृष्टिकोण लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो एक बहुआयामी घटना है। इसके अलावा, अध्ययन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के डिजाइन, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए नीतिगत निहितार्थ प्रस्तुत करता है। पद्धतिगत मोर्चे पर, अध्ययन ज्ञान प्राप्ति, नमूना पर्याप्तता और गतिशील प्रणाली मॉडल की मजबूती के क्षेत्रों में एफसीएम साहित्य को समृद्ध करता है।

प्रमोद के. सिंह (2020) विकासशील देशों में गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को संबोधित करने के लिए कई भागीदारीपूर्ण और समुदाय-मांग-संचालित दृष्टिकोण उभरे हैं। वर्तमान अध्ययन कारण संबंधी तर्क को प्रदर्शित करने के लिए तैनात फजी कॉग्निटिव मैप्स (एफसीएम) की सहायता से भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करता है। यह एफसीएम-आधारित सिमुलेशन के माध्यम से है कि अध्ययन मौजूदा गरीबी उन्मूलन दृष्टिकोण की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है, जिसमें सामुदायिक संगठन आधारित सूक्ष्म-वित्तपोषण, क्षमता और सामाजिक सुरक्षा, बाजार-आधारित और सुशासन शामिल हैं। हमारे निष्कर्ष, कुछ हद तक, गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की संपूरकता की पुष्टि करते हैं जिन्हें व्यापक गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए एक साथ लागू करने की आवश्यकता है। एफसीएम-आधारित सिमुलेशन गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के तत्वों को शामिल करते हुए एक एकीकृत और बहुआयामी दृष्टिकोण लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो एक बहुआयामी घटना है। इसके अलावा, अध्ययन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के डिजाइन, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए नीतिगत निहितार्थ प्रस्तुत करता है। पद्धतिगत मोर्चे पर, अध्ययन ज्ञान प्राप्ति, नमूना पर्याप्तता और गतिशील प्रणाली मॉडल की मजबूती के क्षेत्रों में एफसीएम साहित्य को समृद्ध करता है।

स्वैन, एस.के. (2015) राज्य के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए छठी पंचवर्षीय से दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान ओडिशा राज्य में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया है। इस पेपर में पिछले आठ वर्षों में ओडिशा में लागू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के प्रभाव की परिकल्पना की गई है। अध्ययन ने निर्दिष्ट किया कि कार्यक्रम का लाभार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कार्यक्रम रोजगार सृजन के संबंध में सफल नहीं है क्योंकि कुछ गतिविधियों ने नियमित रोजगार पैदा किया और कुछ अन्य ने लाभार्थियों के लिए मौसमी रोजगार पैदा किया। यह देखा गया है कि भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य वस्तुओं आदि के उपभोग के मानक में सुधार हुआ है। इससे पता चलता है कि एसजीएसवाई ने लाभार्थियों की सामाजिक जागरूकता और जीवन स्तर को विकसित करने में प्रभाव डाला है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 43.86 प्रतिशत लाभार्थी परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ क्योंकि उनकी वार्षिक शुद्ध

www.ignited.in

आय संपत्ति और बचत आदि में वृद्धि हुई। लाभार्थी परिवारों में गरीबी की घटनाओं में गिरावट आई और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

युस्टिनी, टीएन। (2018) इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कृषि व्यवसाय विकास के लिए मूल्य सृजन मॉडल तैयार करना और एक रणनीतिक (नीति) मॉडल का विश्लेषण और डिजाइन करना है जिसे दक्षिण सुमात्रा में गरीबी उन्मूलन के लिए विकसित किया जाना चाहिए। इस अध्ययन का उद्देश्य पालेमबांग शहर में आयोजित किया गया था और ओगन इलिर रीजेंसी जिसने गरीबों की पहचान की वह अभी भी अपेक्षाकृत बड़े हैं। सरकार द्वारा चलाये गये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को मापने के लिए वर्णनात्मक गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण किया गया। गुणात्मक विश्लेषण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करके किया जाता है जो सरकार द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर किए गए, जारी रखे गए हैं और किए जाएंगे। इसके अलावा सामुदायिक सशक्तिकरण के एक ऐसे मॉडल के कार्यान्वयन, निर्माण और विकास में आने वाली समस्याओं या बाधाओं का विश्लेषण किया गया जो गरीबी को दूर करने के लिए काफी प्रभावी माना जाता है। प्रभावशीलता विश्लेषण की गणना नियोजित लक्ष्यों की प्राप्त परिणामों के साथ तुलना करके की जाती है। तैयार और निर्मित मॉडल से ऐसी रणनीतियों और नीतियों को प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है जिन्हें सरकार शहर और ग्रामीण इलाकों दोनों में गरीबी की समस्याओं को दूर करने के लिए अपना सकती है।

लू, शुआंग और लिन (2013) 1989 और 2009 के चीन स्वास्थ्य और पोषण सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए, यह पेपर 1989 और 2009 में चीन में गरीबी और आय असमानता पर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावों की जांच करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों ने एक भूमिका निभाई है गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका, गरीबी दर में लगभग 32% की कमी। हालाँकि, आय असमानता पर प्रभाव उलट गया। उदाहरण के लिए, सरकारी हस्तांतरण के बाद शीर्ष से नीचे आय क्विंटल का अनुपात बढ़ गया, जिससे पता चलता है कि कार्यक्रमों से उच्च आय वाले परिवारों को उनके समकक्षों की तुलना में अधिक लाभ हुआ। समय के साथ क्षेत्रों और आय क्विंटलों के बीच असमानताएं भी बढ़ती गईं।

गरीबी निवारण, रोजगार सृजन और बुनियादी सेवा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

दिसंबर 2000 में 100 प्रतिशत सीएसएस के रूप में लॉन्च की गई, पीएमजीएसवाई का लक्ष्य सभी पात्र असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। भरत मिरमन ने 2009 तक मैदानी इलाकों में 1000 या उससे अधिक की आबादी और पहाड़ी, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक की आबादी वाली सभी बस्तियों को जोड़ने की परिकल्पना की है। मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का व्यवस्थित उन्नयन भी इस योजना का एक अभिन्न अंग है, जो मुख्य रूप से बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों और घरेलू वित्तीय संस्थानों के समर्थन से केंद्रीय सड़क निधि में डीजल उपकर के संचय से वित्त पोषित है। दिसंबर 2005 तक 12ए049 करोड़ रुपये के व्यय के साथ कुल लंबाई 82ए718 किमी. सड़क का कार्य पूरा हो चुका था।

इंदिरा आवास योजना (IAY)

आईएवाई का लक्ष्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और मुक्त बंधुआ मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-एससीध्एसटी बीपीएल परिवारों को मुफ्त में आवास इकाइयां प्रदान करना है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच 75.25 की दर पर लागत-साझाकरण के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। (।ल्) के तहत, मैदानी इलाकों में निर्माण सहायता की सीमा 25000 प्रति यूनिट और पहाड़ीध्कठिन क्षेत्रों के लिए 27ए5007 रुपये हैय और बेकार कच्चे मकान को पक्के में अपग्रेड करने पर 12.500ध्- रुपये है। सभी क्षेत्रों के लिए अर्ध पक्के मकान। 30 जनवरी, 2006 तक 25ए208 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 138 लाख मकानों का निर्माणध्उन्नयन किया गया था।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और संबद्ध योजनाओं के पुनर्गठन के बाद अप्रैल, 1999 में शुरू किया गया एसजीएसवाई, ग्रामीण गरीबों के लिए एकमात्र स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां प्रदान करके स्वरोजगार करने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर

www.ignited.in

लाना है। नवंबर 2005 तक, केंद्र और राज्यों ने 75रू25 के आधार पर लागत साझा करते हुए 8ए067 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिनमें से रु. 62.75 लाख स्व-रोजगारों की सहायता के लिए 6ए980 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए 25 सितंबर, 2001 को शुरू की गई एसजीआरवाई में नकद और खाद्यान्न घटक है, और केंद्र इन दोनों की लागत का 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत वहन करता है और शेष राशि राज्यों द्वारा वहन की जाती है। केंद्रशासित प्रदेश. 2004.05 में, केंद्र द्वारा रु. जारी करने के साथ 82.23 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। नकद घटक के रूप में 4ए496 करोड़ रुपये और राज्योंध्केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 50 लाख टन खाद्यान्न। इसके अलावा, एसजीआरवाई के विशेष घटक के तहत, राज्योंध्केंद्रशासित प्रदेशों को नकद घटकों को पूरा करने के साथ, केंद्र ने 13 आपदा प्रभावित राज्यों को 26 लाख टन खाद्यान्न जारी किया। 2005.06 में नवंबर, 2005 तक, एसजीआरवाई के तहत सृजित मानव दिवसों की संख्या 48.75 करोड़ थी, जबकि जनवरी, 2006 तक नकदी और खाद्यान्न घटकों के संदर्भ में केंद्र का योगदान रु. था। क्रमशः 4651 करोड़ और 35 लाख टन। विशेष घटक के तहत चालू वर्ष में 11 आपदा प्रभावित राज्यों को लगभग 11.65 लाख टन खाद्यान्न जारी किया गया है।

डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) 1973.74 में उन क्षेत्रों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए शुरू किया गया था जो लगातार गंभीर सूखे की स्थिति से प्रभावित थे। मरुस्थलीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए 1977.78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) शुरू किया गया था। बंजर भूमि के विकास के लिए एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (WDP) 1989.90 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

दिसंबर 1997 में, शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईआर) और शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी), जो एसजेएसआरवाई के दो विशेष घटक हैं, को शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए पहले से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के स्थान पर लाया गया। एसजेएसआरवाई को केंद्र और राज्यों के बीच 75रू25 के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। 2003.04 में, रुपये का सेंटफल आवंटन। 94.50 करोड़ से अधिक रु. सिक्किम सहित उत्तरध्पूर्वी क्षेत्र के लिए 10.50 करोड़ रुपये का पूरा उपयोग किया गया। यहां तक कि 2004.05 में भी संपूर्ण बजटीय आवंटन रुपये जारी किये गये। 122.00 करोड़. 2005.06 में, रुपये के आवंटन में से। 160.00 करोड़ रु. 30 नवंबर 2005 तक 84.52 करोड़ का उपयोग किया जा चुका था।

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (ckfCcS)

दिसंबर 2001 में लॉन्च किया गया ट।ड०।ल्, झुग्गीवासियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण और उन्नयन की सुविधा प्रदान करता है, और योजना के एक घटक, निर्मल भारत अभियान के तहत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और सक्षम शहरी वातावरण प्रदान करता है। केंद्र सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है, शेष राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

भारत में गरीबी

गरीबी दुनिया भर में व्यापक रूप से फैली हुई बुराई है, खासकर एशिया और अफ्रीका के देशों में। यह मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत बहुस्तरीय विविधता वाला देश है और यह एक बहुआयामी घटना है। उत्साहजनक विकास अनुभव के बावजूद, देश की सबसे गंभीर और दृढ़ समस्याओं में से एक गरीबी का स्तर और सीमा है। गरीबी का मापन एक जटिल प्रक्रिया है और अनुमान मोटे तौर पर प्रति व्यक्ति व्यय, राज्य घरेलू उत्पाद और वास्तविक कृषि मजदूरी पर स्वतंत्र साक्ष्य के अनुरूप हैं। भारत की गरीबी का अध्ययन आज बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए विभिन्न सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कई उपाय किए गए हैं, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के विशाल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद है। 2011.12 में तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार, 21.9 प्रतिशत आबादी गरीब है यानी 269.9 मिलियन आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। विश्व स्तर पर विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या मापी गई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है

समिति	वर्ष	गरीबी अनुपात			गरीबों की संख्या (मिलियन)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
रंगराजन	2011-12	30.9	26.4	29.5	260.5	102.5	363
	2009-10	39.6	35.1	38.2	325.9	128.7	456.6
कमी		**8.7**	**8.7**	**8.7**	**65.4**	**26.2**	**91.6**
तेंडुलकर	2011-12	25.7	13.7	21.9	216.7	53.1	269.8
	2009-10	33.8	20.9	29.8	278.2	76.5	354.7
कमी		**8.1**	**7.2**	**7.8**	**61.5**	**23.4**	**84.9**

उपरोक्त से पता चलता है कि वर्ष 2009.10 और 2011.12 में रंगराजन और तेंदुलकर समिति द्वारा मापी गई भारतीय गरीबी। रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी अनुपात 30.9% (260.5 मिलियन गरीब लोग) और शहरी गरीबी अनुपात 26.4% (102.5 मिलियन गरीब लोग) था और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 29.5% (363 मिलियन लोग) है। वर्ष 2011.12 में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में 39.6% (325.9 मिलियन गरीब लोग) और शहरी क्षेत्रों में 35.1% (128.9 मिलियन गरीब लोग) और 2009.10 में दोनों क्षेत्रों में 38.2% (456 मिलियन गरीब लोग)। 2009.10 से 2011.12 तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में औसतन 8.7% (65.4 मिलियन लोग) और 8.7% (26.2 मिलियन लोग) कुल 8.7% (91.6 मिलियन लोग) की गिरावट आई है।

रोजगार परिदृश्य

विभिन्न योजना अवधियों के तहत भारतीय आर्थिक विकास में उत्पादन की वृद्धि दर को कभी भी रोजगार की वृद्धि दर के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। त्वरित आर्थिक विकास हमेशा भारतीय योजनाकारों का पसंदीदा पाया गया है। पहली योजना से ही आर्थिक विकास की यह अवधारणा रोजगार के अवसर में वृद्धि, आय असमानता और गरीबी में कमी के साथ बहुत अधिक जुड़ी हुई थी, इस बात पर प्रारंभिक बहस थी कि आय असमानता में कमी विकास के लिए अनुकूल थी या नहीं। यह माना गया कि आय असमानता में कमी से बचत में कमी आएगी और इसलिए एलडीसी में पूंजी निर्माण धीमा हो जाएगा, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा।

योजनाओं	वार्षिक जीडीपी विकास दर (स्थिर मूल्य पर)	रोजगार की वृद्धि
प्रथम योजना (1951-56)	3.7	0.39
दूसरी योजना (1956-61)	4.2	0.87
तीसरी योजना (1961-66)	-3.8	2.03
चौथी योजना (1969-74)	3.4	1.99
पाँचवीं योजना (1974-78)	5.0	1.84
छठी योजना (1980-85)	5.5	1.89
सातवीं योजना (1985-90)	3.6	1.26
आठवीं योजना (1991-96)	6.7	1.86
नौवीं योजना (1997-2002)	7.7	1.14
दसवीं योजना (2002-2007)	7.2	1.23
ग्यारहवीं योजना (2007 -2012)	7.5*	1.82*

क्षेत्रवार रोजगार की वृद्धि

सार्टोरियल बेस यानी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार सृजन यह ठीक है कि पूर्व सुधार और सुधार अवधि में रोजगार के अवसर का रुख बढ़ने की प्रवृत्ति में है। निम्नलिखित तालिका सार्टोरियल बेस में रोजगार की वृद्धि को दर्शाती है

आर्थिक क्षेत्र	मिलियन में रोजगार उत्पन्न हुआ			
	1983	1993	2000	2010
प्राइमरी सेक्टर	208.99 (69.0)	245.16 (65.5)	239.83 (60.4)	228.43 (55.07)
द्वितीयक क्षेत्र	41.66 (13.8)	55.53 (14.8)	66.91 (16.8)	78.12 (18.82)
तृतीय श्रेणी का उद्योग	52.11 (17.2)	73.76 (19.7)	90.26 (22.7)	108.35 (26.11)
कुल रोजगार	302.76 (100)	374.45 (100)	397.0 (100)	414.90 (100)

एनएसएस डेटा से प्राप्त बेरोजगारी और श्रम बल की वृद्धि दर उपरोक्त तालिका में दी गई है, निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।

प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन और अन्य उत्पादन इकाई में रोजगार की वृद्धि दर 69% से घटकर 55.07% हो गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अधिकांश आबादी ग्रामीण भारत में रही, लेकिन रोजगार के अवसरों में 14.03% की गिरावट आई है। यह क्रय शक्ति समानता, शहरी क्षेत्र की ओर अनिवार्य गतिशीलता आदि में गिरावट को प्रभावित करता है।

द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि 13.8% से बढ़कर 18.82% हो गई। यह प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में जनसंख्या के स्थानांतरण के संबंध में विकास सिद्धांत का एक संकेत है।

www.ignited.in